

संपादकीय

गुणवत्ता की हकीकत

बताएं उपभोक्ताओं को

अन्धकारियों की आक्रामक मार्केटिंग व विज्ञापनों में खेल से भारत में बच्चों के विकास के लिए जरूरी पोषक पदार्थों को बेचने का उद्गम देश में दशकों से चला आ रहा है। इस प्रचार के खेल में फिल्मों व ग्लैमर की दुनिया की हस्तियां मोटी रकम लेकर शामिल हो जाती हैं। विव्हेनटा यही है कि देश का आम उपभोक्ता देशी-विदेशी खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियों के उमड़ता दावों पर भरोसा कर लेता है, जिसमें बच्चों के तेज विकास, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा दिमाग तेज करने के वादे किए जाते रहें हैं। लेकिन वास्तव में माता-पिता को इन दावों के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने के लिए, न कि लुभावने विज्ञापन। शिशुओं के विकास के लिए बनाए गए फार्मूले और कॉम्प्लान से संबंधित दावों को लेकर नेस्ले इंडिया और जाइडस वेलनेस को भारतीय खाद्य संस्थान जैसे मानक प्रधिकरण यानी एफएसडीएआई द्वारा नोटिफ़ेस जारी किए गए, जिसमें उपोषण संबंधी दावों की विश्वसनीयता और सख्त नियामक नियमनारी की आवश्यकता पर फिर सावाल खड़े कर दिए हैं। नियामक ने कॉम्प्लान के शिशुओं के तीव्र गति से विकास और एकग्रता, स्मृति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित लाभ जैसे दावों के उल्लेख समाप्त उठाए हैं। नियामक ने नेस्ले को उसके शिशु आहार के फार्मूले में खास प्रोटीन की पाचन क्षमता और मां के दूध के समान रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक लाभों को प्रमाणित करने के लिए कहा है। नेस्ले ने इन्हें, उदाहरण दीवती समथ एसे के दावों के माता-पिता के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से जब बच्चे के विकास को लेकर चिंताएं परिवार को बेबेहतर पोषण के वादों के प्रोत्साहनशील बनाती हैं। इस मामले में एक शोध मॉडिया इन्स्टीट्यूट द्वारा ऑनलाइन प्रचार की थोड़ी जांच की गई, जिसमें शिशु आहार फार्मूला उत्पादों की गुणवत्ता की रैंकिंग की गई। इसमें पाया कि पाचन क्षमता या कि इसके उपयोग से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मस्तिष्क के विकास और पाचन में लाभ मिलता है। आमतौर पर ऐसे प्रचारकों मोटी फीस लेकर उपभोक्ताओं को ठगने पहुंचने का ही काम करते हैं।

असह्य, इस प्रकार के बाद डिज़ालेड विज्ञापनों के नियमन की बढ़ती चुनौती भी सामने आती है। दरअसल, ऐसे भ्रामक व्यावसायिक प्रचार से कभी-कभी वास्तविक लाभ देने वाली सलाह होने का भ्रम भी पैदा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि 'शिशु दुग्ध' विनिर्देश अधिनियम' के तहत लगाई गई पाबंदियों विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका मकसद शिशुओं को मां का दूध देने से स्वास्थ्यकारी प्रथा का अनुचित व्यावसायिक प्रभावों से होने वाले नुकसान से बचना है। वैसे देखें तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिए गए ये नोटिस मुनाफ़े के लिए किए जा रहे किसी गैरतक्य के अंतिम निष्कर्ष नहीं कहे जा सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकरण में कंपनियों की भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर, उनके बड़-बड़कर किए जा रहे सारे वाले दावों की जांच विनियमों खुशबू और नियमों के आधार पर ही की जानी चाहिए। हालाँकि, प्रकरण के नियामकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना तार्किक आधार वाले या गुमराह करने वाले दावों को उत्पाद बनाने वाली कंपनियों द्वारा तुरंत नकारना जाए। वहीं दूसरी ओर, नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादकों पर उचित करवाई की जाए। वैसे तो हमारे देश में आमतौर पर खाद्य उत्पादों के लेबल और विज्ञापन ही अक्सर उपभोक्ताओं के लिए जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों व अशिक्षित लोगों में यह समस्या ज्यादा प्रतीती है। इसलिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को अपनी जांच-पड़ताल सख्ती से करनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रवर्तन एजेंसियों के नतीजे सामने आने पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ ही, भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निम्ता किसी उत्पाद को बाज़ार में उतारने से पहले अपने दावों को सच्चाई की कसौटी पर सही साबित करे। निश्चित रूप से पोषण संबंधी मकेडिंग का मकसद निश्चित रूपसे देना होना चाहिए, न कि गैरतक्य लोगों को गुमराह करना।

आभेयान

द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत प्रतीक है चामुंडेश्वरी मंदिर, शिखर पर विराजमान हैं सात स्वर्ण कलश

कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर मैसूर की परंपराओं का राजमहलों, संस्कृतिकृतियों, पहाड़ों और नग्न मंदिरों से जुड़ा है। इन्होंने धार्मिक स्थलों में चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर चामुंडेश्वरी पर स्थित श्री चामुंडेश्वरी मंदिर विशेष प्रसिद्धि हासिल की है। समुद्र तल से लगभग 3,489 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर मां चामुंडेश्वरी के शक्तिशाली स्वरूप को समर्पित है। इसकी मुख्य वास्तुकला, धार्मिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाओं के राजपरिसर से जुड़ा इतिहास अलग-अलग देशों के प्रमुख तीर्थस्थलों में स्थान दिलाते हैं। चामुंडेश्वरी के ऊंचे प्रवेश द्वार और उसके शिखरों पर स्थित सात स्तंभ कलश श्रद्धालुओं को आकर्षण का केंद्र हैं। पहाड़ी की ऊंचाई से दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य और मंदिरों पर आधारित सांख्यिकीय वातावरण बस आने वाले यात्रियों के लिए एक अलग अनुभूति प्रदान करता है। नवगिरि के दौरान इस प्रमाण में विशेष धार्मिक उत्साह दिखाई देता है और चामुंडेश्वरी से श्रद्धालु द्वारा के दर्शन के लिए प्रेरित होते हैं।

श्री चामुंडेश्वरी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की प्राचीन स्थापत्य परंपरा और धार्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। यहां देवी की उपासना के साथ सदियों पुरानी मान्यताओं, राजपरिवार की भक्ति और स्थानीय परंपराओं का सुंदर संगम देखने को मिलता है। मंदिर की पहचान इसके भव्य गोपुरम, गर्भगृह, मंडपों और

प्राइड शैली में निमित्त वास्तु संरचना से होती है। पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण इसका धार्मिक और भौगोलिक महत्व भी विशेष माना जाता है।

श्री चामुंडेश्वरी देवी को हमें चामुंडी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमें दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। देवी की आराधना शक्ति साहस और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में की जाती है। पौराणिक कहानों के अनुसार, महिषासुर नामक असुर ने अपर्न शक्ति के मद में देवताओं और पृथ्वी पर आश्वत्थार करना शुरू कर दिया था। उसने केशव आतंक से परेशान देवताओं ने देवी शक्ति की आराधना की। इसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का सामना किया और तलें संघर्ष के बाद उसका वध कर दिया। इसी विजय के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है।

मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों को इसी पौराणिक प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार, महिषासुर का वध ईर्स क्षेत्र में हुआ था। पहाड़ी के निम्न महिषासुर की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो इस कथा की स्मृति को जीवित करती है। इस प्रतिमा और मंदिर के आसपास का धार्मिक परिवेश पर्यटकों को मैसूर की पौराणिक पहचान से परिचित कराता है। देवी के नाम चामुंडी और चामुंडेश्वरी का संबंध भी उनकी

शक्ति और दृष्ट शक्तियों के निवासस्थान के स्वरूप से जोड़ा जाता है। भक्त माँ के दरबार में सुख-समृद्धि, परिवार को खुशहाली और संकटों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। कर्नाटक के मैसूर शहर से दिखाइ देने वाले चामुंडी पहाड़ियों धार्मिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर को क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। पहाड़ी तलहट्टी के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध है और यहां सिंदूरियों के रास्ते भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। सभितों से मंदिर तक जाना की परंपरा उपर्युक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है, जहाँ अपनी यात्रा को धार्मिक साधना और श्रद्धा जोड़कर देखते हैं।

प्राचीन धार्मिक साहित्य में इस क्षेत्र पर उल्लेख त्रिमुक्ता क्षेत्र के रूप में भी मिलता है। धार्मिक परंपराओं में चामुंडी पहाड़ियों को देवी उपासना और शिवार्थित से जुड़ा पवित्र स्थान माना गया है। मंदिर के अतिरिक्त स्थिति महालेख्य मंदिर भी शक्ति महत्त्व रखता है। महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे चामुंडी पहाड़ियों के प्राचीन धार्मिक स्थलों में शामिल किया जाता है। इस प्रकार पहाड़ी शक्ति में शक्ति और शिव उपासना की परंपराएं एक साथ दिखाई देती हैं।

मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु देवी की पूजा-अर्चना करने के साथ पहाड़

के प्राकृतिक तातावरण का भी अनुभव कर रहे हैं। ऊँचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ मौसम ठंडा है। कित्नुत दुर्घट दिखाई देते हैं। धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का यह मेल इस स्थल को पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय बना है। विप्लव अदसरसेर में मंदिर में पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और उसका आयोजन होता है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं।

चामुंडेश्वरी मंदिर के वर्तमान स्वरूप और इसकी भव्यता के विकास में मैसूर के वैद्येश्वर राजगिरियार का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मैसूर के शासक मां चामुंडेश्वरी व अपनी आराध्य देवी मानते थे। राजगिरियार की धार्मिक आस्था के कारण देवी की पूजा के विषय राजकीय महत्व प्राप्त हुआ। समय-विशेष पर मंदिर के विकास, रमण और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए।

महाराज कृष्णराज वैद्यराज तृतीय का निशान मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास से निशान रूप से जोड़ा जाता है। वर्ष 1827 में मंदिर के क्षेत्र के व्यापक जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर निर्मित भव्य सा मंजिला गोपुरम् इसकी वास्तुकला का प्रमुख आकर्षण है। गोपुरम् दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशिष्ट पहचान माने जाते हैं। इनके निर्माण के विप्लव प्रवेश द्वार को भवन बनाने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर की धार्मिक प्रतिष्ठा

और स्थापत्य साँदव को प्रदर्शित करने लिये भी किया जाता है।
वोडेश्वर राजपरिवार की देवी के प्रति श्रद्धा का प्रभाव मैसूर की सांस्कृतिक परंपराओं में भी दिखाई देती है। दशरथा उत्सव के दौरान चामुंडेश्वरी देवी की पूजा विशेष महत्त्व रखती है। मैसूर दशरथा अंगण में भव्य उत्सव धार्मिक आयोजनों और ऐतिहासिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उत्सव में देवी व आराधना और राजपरिवार से जुड़ी धार्मिकता का विशेष स्थान है। मंदिर से जुड़ी धार्मिक गतिविधियाँ इस सांस्कृतिक विरासत व आज भी जीवित रखती हैं।
श्री चामुंडेश्वरी मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारत की पारंपरिक द्रविड़ शैली व विशेषताओं को दर्शाती है। इस शैली में ऊँचे गोपुरम्, मंडप, गर्भगृह और धार्मिक प्रतीकों से सज्जित संरचनाओं का विशेष महत्व होता है। मंदिर का प्रवेश द्वार काफी ऊँचाई और बहुस्तरीय बनावट के कारण दूर से भी ध्यान आकर्षित करता है। सामंजस्यपूर्ण गोपुरम् विभिन्न स्तरों में सजावटी आकृतियों व पारंपरिक स्थापत्य तत्व दिखाई देते हैं, जिनसे दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण की कलात्मक परंपरा का परिचय देता है।
मंदिर परिसर की संरचना में प्रवेश द्वार आगे बढ़ते हुए विभिन्न धार्मिक और स्थापत्य भागों दिखाई देते हैं। इनमें नगरों में प्रचलित प्राकार, अंतर्गत मंडप और मुख्य गर्भगृह

मूख हैं। नवग्रह मंडप मंदिर के धार्मिक गतिविधियों और पूजा परंपराओं में जुटा महत्त्वपूर्ण भाग है। प्राकार मंदिर अंतरिक क्षेत्र को व्यवस्थित करने वाला संरचना है, जबकि अंतर्गता मंडप गमना और बाहरी मंडप के बीच स्थित होने के मुख्य गर्भगृह वह पवित्र स्थान है, जहां देवता/देवियों की प्रतिमा स्थापित है और भक्त श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। गर्भगृह के ऊपर निर्मित विमान भी मंदिर की स्थापत्य विशेषताओं में शामिल है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में विमान धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व को प्रतिबिंबित करता है। गमना और विमान की बनावट अंतर हो सकती है। दोनों मंदिर की समग्र संरचना में विशेष पद्धति प्रदान करते हैं। मंदिर संरचना में, मंडपों की व्यवस्था और शिखर संरचना मिलकर इसकी पारंपरिक स्थापत्य विशेषता को उजागर करते हैं। देवता/देवियों के मंदिर के शिखर पर स्थापित सन्यासियों कलश इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्थित ये कलश श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करते हैं और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारतीय मंदिर परंपरा में कलश को शुभ संकेत और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों के शिखर पर कलश स्थापित करने की परंपरा प्राचीन स्थापत्य और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है।

का समझन का लिए समाजवादी पाठ्य
 अंतर्निवेशों और उत्तर प्रश्न के बदलते मुद्दे
 नेतृत्व के संकेत को देखना जरूरी है। पिछले
 कुछ समय से यह चर्चा आम थी कि आज
 समाज के जेल जान और उनके परिवार पर का
 कानूनी संकट के दौरान समाजवादी पार्टी का
 आक्रामकता के साथ उनका साथ नहीं देना
 जिसकी ओर एक संस्थापक सदस्य को ले
 है। पार्टी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर
 सुगुनाहट थी कि अखिलेश यादव अपनी छ
 को एक नए, आधुनिक और गैर-विवादास्पद
 रूप में बदलने के लिए 'मौड़ी' (मुसल
 यादव) समीकरण से थोड़ा इतर (पिछला
 (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा
 रहे हैं। इस नए दिशाओं में आजान साथ
 पुराने समाजवादी दिशाओं की कट्टर छवि प
 निती से बच जाये। इसी बीच, असदुल्ला ओवे
 की एआईएमआईएम और अन्य क्षेत्रीय दलों
 इस खालीपन को भरने की कोशिश शुरू क
 है। ओवेसीयों लगातार यह आरोप लगाते रहे
 सपा मुस्लिमों के वोट तो लेती है, लेकिन ज
 उनके बड़े नेताओं पर संकट आता है, तो नेतृ
 चुपी साज लगा है। परिचय में उत्तर प्रदेश,
 कभी आजान समाज का अपेक्षा लिफा माना जा
 था, वहां मुस्लिम मतदाताओं के बीच उप
 इस अमरसंज्ञक को अखिलेश यादव पांच उ
 है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव और भा
 बाद के घटनाक्रम में जिस तरह से अंशरू
 गुटबाजी सामने आई, उसने पार्टी अलाक

का जोड़ो। भूल हो आत्म खान खुद गुनाह में पतन होना बज्र के, लेकिन उनका रसि-
कट्रोल यूपी की सिवास में बेहद प्रभावी रह
जाला है। उनका यही प्रभाव अखिलेश यादव
को उनके पास खींच लाया, क्योंकि वे जान-
ते कि यूपीमें उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज
में आज़म खान की आवाज़ आज भी
भावनात्मक अपील रखती है, जिसे दूसरे दूर
नेता रिप्लेन नहीं कर पायें। यह प्रभाव केवल
रामपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि मुरादाबाद
जिलानौर, बेरौली और अमरोहा जैसे पूरे मुस्लिम
बहुल बेल्ट में आज खान की राजनीति का
छाछला आज भी डिमांडथिंगों के भाव्य
फैसला करने की क्षमता रखती है। दूसरे
तरफ़, इस मुलाकात ने विशिष्टी खेमे, विशिष्ट
भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सफ़र
पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। अगर
ने इसे "तुष्टिकरण की राजनीति का न
अवयव" और "अपराधियों को संरक्षण देने का
कोशिश" करार दिया है। सस्ताभाई दल का यह
है कि कानून सम्मत कार्रवाई के तहत जेल
में बंद एक राज्यायता नेता से राज्य के
मुख्यमंत्रि की यह मुलाकात यह दाशती है।
समाज आज भी अनासुर पुरेने और तुष्टिकरण
की नीति से बाहर नहीं निकल पाई है। भाजपा
के रणनीतिकार इस मुलाकात को बृहस्पत्य
तदतिपा के बीच भुगाने की कोशिश करे
मल्लिदास को के खिलाफ एक बार फिर धुर्वेक
का माहौल बनाया जा सके

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) ,7096333307
Email:navsarjansanskriti2016@gmail.com*navsarjansanskriti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskriti.com

सूरत में 27 अक्टूबर को जल संकट, तीन जेन की 10 लाख आबादी होगी प्रभावित

डिंडोली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के भूमिगत टैंकों की होगी सफाई, कई इलाकों में सुबह से रात तक बंद रहेगी सप्लाई; कहीं कम दबाव से मिलेगा पानी

सूरत। सूरत महानगरपालिका की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण सफाई कार्य किया जाएगा। महानगरपालिका के हाइड्रोलिक विभाग द्वारा लिंबायत क्षेत्र स्थित डिंडोली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के भूमिगत टैंकों की सफाई की जाएगी। इसके चलते लिंबायत, उधना जोन-ए और कनकपुर जोन के अनेक रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। कुछ इलाकों में जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहने, जबकि अन्य क्षेत्रों में कम दबाव और कम मात्रा में पानी मिलने की संभावना है। इस कार्य से तीनों जोन की करीब 10 लाख आबादी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में महानगरपालिका ने नागरिकों से निर्धारित तारीख के लिए पानी का पर्याप्त भंडारण करने और उसका ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करने की अपील की है। महानगरपालिका के अनुसार, डिंडोली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के भूमिगत टैंकों की सफाई जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव

दक्षिण कोरिया में उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज 10 महत्वपूर्ण वन-टू-वन और राउंडटेबल बैठकों सहित बिजनेस सेमिनार का आयोजन होगा

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अंतर्गत गुजरात में वैश्विक निवेश तथा औद्योगिक साझेदारी को नई गति देने के लिए दक्षिण कोरिया की यात्रा पर पहुँचे गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संचयी के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज सियोल में विभिन्न वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों के साथ लगभग 10 महत्वपूर्ण वन-टू-वन और राउंडटेबल बैठके आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, दिन के अंत में कोरियाई उद्योग जगत के साथ एक विशेष बिजनेस सेमिनार और डिनर का आयोजन किया गया है।

आज के निर्धारित कार्यक्रमों और बैठकों का मुख्य विवरण निम्नासुक्त रहेगा :

एडवार्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के साथ बैठक : दिन की शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल एटीसीए के सीईओ एवं चेयरमैन श्री जेजोंग ली तथा

का हिस्सा है। इस दौरान संबंधित ओवरहेड टैंकों से जुड़े क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। अलग-अलग इलाकों में पानी बंद रहने या कम दबाव से मिलने की स्थिति उनके संबंधित टैंक और आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करेगी। इसलिए सभी प्रभावित क्षेत्रों में एक जैसी स्थिति रहने के बजाय कहीं पूरी तरह पानी बंद हो सकता है, तो कहीं सीमित मात्रा में जलापूर्ति जारी रह सकती है। सफाई कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य होने की स्थिति संबंधित व्यवस्था पर निर्भर करेगी। शहर के तेजी से विकसित हो रहे लिंबायत और डिंडोली क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासीय सोसायटियां और घनी आबादी वाले मोहल्ले हैं। यहां पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू कामकाज, खाना बनाने, सफाई और अन्य दैनिक ज़रूरतों पर असर पड़ सकता है। इसी तरह गोडादरा, पर्वत, भेस्तान, बमरोली और कनकपुर से जुड़े क्षेत्रों में भी नागरिकों को पहले से तैयारी करनी होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होने से वहां



की दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका है। लिंबायत और डिंडोली क्षेत्र में भक्तिनगर, रॉयल पैलेस, शुभवाटिका, प्रियंका सिटी-1 और 2, शिव दर्शन, गायत्री नगर, खोडियार नगर, श्रद्धा सोसायटी, सुमुख सकल, मानसी रेजीडेंसी, मोदी एस्टेट, मोर्चा नगर, योगेश्वर पार्क, राधाकृष्ण, गांधीनगर, प्रियंका सोसायटी, चेतन नगर, ठाकोर नगर, ओमनगर, मिलेनियम पार्क, उमिया बंगला, अंबिका नगर-1 और 2, मधुरम सकल,

तिरुपति नगर, कृष्णकुंज, सरस्वती नगर और महादेव नगर-1 से 5 सहित कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। महाराणा प्रताप सोसायटी, प्रियंका-3 और 4, नीलकंठ नगर, देवी दर्शन, ऋषि नगर तथा प्रियंका मेगासिटी के निवासियों को भी पानी का इंतजाम पहले से करने की सलाह दी गई है।

पर्वत और आसपास के इलाकों में भी जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। पर्वत गांव, उमिया नगर, पुरुषोत्तम नगर, चंदलोक सोसायटी, स्मि्त रो हाउस, ठाकोर नगर, माहेश्वरी पार्क, गृहस्वन्, सहजानंद, महादेव नगर, डी.के. नगर, रत्नप्रभा, कल्पना नगर, कैलाश नगर, शिवकृपा और कुबेर नगर में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा सुपर सिनेमा रोड की सोसायटियां, द्वारकेश नगर, रोशनी नगर, जिनेश नगर, प्रियंका सिटी प्लस, जे.बी. नगर, लक्ष्मी पार्क, ध्रुव पार्क, गुरुनगर, वीरदर्शन, हरे जाणी।

लोड्डे वेलफूड : खाद्य एवं कम्पैक्शनरी क्षेत्र की वैश्विक कंपनी लोड्डे वेलफूड के ग्लोबल बिजनेस हेड श्री चो क्यूंग वून के साथ विस्तार को लेकर बैठक आयोजित होगी।

कॉस्मैक्स मुख्यालय का दौरा : ब्यूटी और हेल्थकेयर उत्पादों के वैश्विक अग्रणी निर्माता कॉस्मैक्स के मुख्यालय का दौरा कर वाइस चेयरमैन के साथ बैठक की जाएगी।

कोरियाई स्टार्टअप्स राउंडटेबल : दक्षिण कोरिया के उभरते स्टार्टअप्स के साथ गुजरात में नवाचार और इकोसिस्टम विकसित करने के विषय पर विशेष राउंडटेबल आयोजित होगी।

कांिया बायो राउंडटेबल : बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों यूएमटीआर, प्लैटनरऔर बेरियम के सीईओ के साथ राउंडटेबल चर्चा की जाएगी।

गुजरात में ई-नाम पोर्टल से 8.87 लाख से अधिक लोग जुड़े 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कृषि उत्पादों की बिक्री

ई-नाम से किसानों को हुआ आर्थिक लाभ, उपलेटा मार्केट समिति के हरीश घोडासरा की आय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि

गांधीनगर, 23 अक्टूबर : कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारस्तंभ है और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज टेक्नोलॉजी के उपयोग से किसानों के लिए बाजार तक पहुँच और बिक्री की प्रक्रिया सरल बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेकर वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) पोर्टल लॉन्च किया था, जो कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। गुजरात में ई-नाम पोर्टल से 8.87 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें 8,69,922 किसान, 10,291 व्यापारी, 7,191 कमीशन एजेंट और 461 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) शामिल हैं।

ई-नाम पर राज्य की 144 मंडियाँ एकीकृत, 12,000 करोड़ रुपए से



अधिक के कृषि उत्पादों की बिक्री मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किसानों को कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर अवसर मिल रहे हैं। ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचकर अधिक खरीदारों तक पहुँच सकते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। राज्य की 144 मंडियाँ ई-नाम पोर्टल से जुड़ी

हुई हैं। अब तक गुजरात में ई-नाम के माध्यम से 12,740.60 करोड़ रुपए मूल्य के 3.20 करोड़ क्विंटल से अधिक कृषि उत्पादों की बिक्री हुई है।

ई-नाम (ई-नाम) क्या है ? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न एपीएमसी मंडियों को एक ही बाजार व्यवस्था के साथ जोड़ता है। कृषि मंत्रालय अंतर्गत स्मॉल फार्मर्स

एपीबिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) द्वारा संचालित यह प्लेटफॉर्म कृषि उत्पादों की बिक्री की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाता है। यह बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के साथ मांग तथा आपूर्ति के आधार पर उत्पादों के बाजार भाव जानने में भी मदद करता है। ई-नाम से किसानों को पारदर्शी नीलामी, गुणवत्ता के अनुसार दाम और समय पर ऑनलाइन भुगतान का लाभ मिलता है।

ई-नाम से उपलेटा मार्केट समिति के हरीश घोडासरा की आय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई

उना मार्केट समिति के परबतभाई पटाल पिछले एक वर्ष से ई-नाम के माध्यम से मूंगफली बेच रहे हैं। परंपरागत स्थानीय बाजार की तुलना में ई-नाम पर बिक्री की प्रक्रिया तेज है और उन्हें प्रत्येक बिक्री पर 200 से 500 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके अनुसार इसके परिणामस्वरूप उनकी कुल आय में लगभग 5 से 7

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 15वें ‘इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-उद्यम 2026’ का शुभारंभ कराया

500 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा 12 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एवं उत्पादों का प्रदर्शन

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 23 से 26 अक्टूबर, 2026 तक लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित किए जा रहे इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-उद्यम 2026 का शुक्रवार को गांधीनगर स्थित हेलीपैड इवेंट एंजीविशन सेंटर में शुभारंभ कराया। इस भव्य औद्योगिक मेले के द्वारा एमएसएमडी क्षेत्र के उद्योगों, स्टार्टअप्स, निर्माताओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार करने वालों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर परस्पर सहयोग साधकर व्यावसायिक जुड़ावों को विकसित किया जाएगा।

यह फेयर गुजरात रीजन के सबसे बड़े एक्सपो के रूप में इंजीनियरिंग से लेकर हस्तशिल्प तक के प्रत्येक क्षेत्र के एमएसएमडी इकोसिस्टम को एक ही छत्र तले लाने वाला विशाल एक्सपो है। इस मेले में देशभर से आए 500 से



अधिक प्रदर्शकों द्वारा 12 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक, उत्पादों और औद्योगिक उद्यमों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही बिजनेस नेटवर्किंग, निवेश संबंधी चर्चाओं, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन सत्रों

और आधुनिक औद्योगिक प्रस्तुतियों के साथ-साथ बीटूबी तथा बीटूजी बैठकों का भी आयोजन किया गया है। लघु उद्योग भारती का यह एक्सपो एमएसएमडी, इन्वोवेशन्स, उद्यमिता और आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त मंच

भावना पार्क-1 और 2, शिवपार्क, देवीकृपा, वृंदावन, महाप्रभुनगर रो हाउस, केसरभवानी, मधुसूदन, शामला रो हाउस, पटेल नगर, कृष्णपार्क और असर नगर में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। महाराणा प्रताप सोसायटी, प्रियंका-3 और 4, नीलकंठ नगर, देवी दर्शन, ऋषि नगर तथा प्रियंका मेगासिटी के निवासियों को भी पानी का इंतजाम पहले से करने की सलाह दी गई है।

पर्वत और आसपास के इलाकों में भी जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। पर्वत गांव, उमिया नगर, पुरुषोत्तम नगर, चंदलोक सोसायटी, स्मि्त रो हाउस, ठाकोर नगर, माहेश्वरी पार्क, गृहस्वन्, सहजानंद, महादेव नगर, डी.के. नगर, रत्नप्रभा, कल्पना नगर, कैलाश नगर, शिवकृपा और कुबेर नगर में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा सुपर सिनेमा रोड की सोसायटियां, द्वारकेश नगर, रोशनी नगर, जिनेश नगर, प्रियंका सिटी प्लस, जे.बी. नगर, लक्ष्मी पार्क, ध्रुव पार्क, गुरुनगर, वीरदर्शन, हरे

गुजरात की यात्रा पर आए स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी ने गांधीनगर स्थित बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया

श्री जॉन स्विनी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद कर शिक्षा, मानव अनुसंधान और लाइफ-साइंस क्षेत्र में सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की

गांधीनगर : स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी गुजरात की यात्रा पर आए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित वैश्विक स्तर की गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के साथ साझेदारी को लेकर चर्चा की। साथ ही; श्री जॉन स्विनी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद करके शिक्षा, रिसर्च और लाइफ-साइंस क्षेत्र में सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के स्नातक श्री जॉन ने अपने कॉलेज के समय के अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए। श्री जॉन स्विनी ने कहा कि स्कॉटलैंड और भारत के बीच आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ स्कॉटिश

कृष्ण, माधव बाग और नंदनवन में भी पानी की आपूर्ति कम दबाव से हो सकती है। स्काई व्यू हाइट्स, स्काईलोम हाइट्स और सफायर-8 सहित आसपास की आवासीय सोसायटियों को भी अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्था करनी होगी। कनकपुर जोन के अंतर्गत अन-पश्चिम, भिंडी बाजार, अन गमवल, साई मोहन सोसायटी, वी-4 और आसपास के क्षेत्र, राहतनगर, तिरुपति बालाजी सोसायटी, गभेनी, रामेश्वर इंडस्ट्रीज और सोमनाथ नगर में जलापूर्ति प्रभावित रह सकती है। डुंडीगाम, डिप्लोयाम, प्राइम प्वाइंट, अनुपम सिटी, वडोदगाम, वडोद आवास, आशीष नगर, बापूनगर, गणेश नगर और आकाश पृथ्वी अपार्टमेंट के लोगों को भी पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होगी। साईमोहन-1 और 2, महावीर नगर, रामनगर, कृष्णनगर, गजानंद संकुल तथा ओम इंडस्ट्रीज के आसपास के क्षेत्रों में भी आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है। भेस्तान, बमरोली और आसपास

के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में आवासीय सोसायटियां प्रभावित होने की आशंका है। न्यू बमरोली की अमिधारा सोसायटी, उमिया रेजीडेंसी, आस्था रेजीडेंसी, श्लोक आर्कड, ओम कॉम्प्लेक्स, तुप्लि नगर, लक्ष्मी नगर, जयअंबे सोसायटी, सुखी नगर और जयकृष्ण नगर-1 व 2 में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। अमृतनगर तथा आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में भी असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा आवास भेस्तान, शांतिवन रेजीडेंसी, प्रयोषा रेजीडेंसी, उम्मीद नगर, उत्सव एन्क्लेव और भेस्तान से भनोदरा रेलवे ट्रैक के पूर्व के क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित रह सकती है। जियाव, बुडिया गांव, सोनारी गांव, साई नगर, आनंदो होम्स, बमरोली गाम, गीतानगर, हरसिद्धि नगर, तुलसीधाम सोसायटी, रवि नगर, सत्यनारायण नगर, जयअंबे नगर, रामेश्वरम ग्रीन, रामेश्वरम हिल्स, श्रृंगाल रेजीडेंसी, मराठा नगर, कैलाश नगर और सदर सोसायटी सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को भी पहले से पानी

जमा करने की सलाह दी गई है। महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे 27 अक्टूबर को होने वाली संभावित कटीौत को ध्यान में रखते हुए घरों में पीने, खाना बनाने, स्नान और अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए पर्याप्त पानी जमा कर लें। पानी का उपयोग सावधानी और ज़रूरत के अनुसार करें, ताकि आपूर्ति प्रभावित रहने के दौरान अनावश्यक परेशानी न हो। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों वाले परिवारों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। सफाई कार्य के दौरान नागरिकों से सहयोग करने की अपील भी की गई है। शहर की बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाली इस व्यवस्था के मद्देनजर नागरिकों के लिए ज़रूरी है कि वे अपने क्षेत्र की जलापूर्ति की स्थिति पर ध्यान दें और किसी भी संभावित कमी के लिए पहले से तैयारी रखें। भूमिगत टैंकों की सफाई पूरी होने के बाद जलापूर्ति सामान्य होने की प्रक्रिया संबंधित वितरण व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ेगी।

गुजरात की यात्रा पर आए स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी ने गांधीनगर स्थित बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया



के क्षेत्र में भी दोनों देश आपसी सहयोग से काम करेंगे। इस यात्रा के दौरान गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर (इन चार्ज), डॉन (एकेडमिक्स) और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. राकेश रावल तथा यूके गवर्नमेंट के गुजरात और राजस्थान के लिए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त श्री स्टीव हिकलिंग उपस्थित रहे। इसके अलावा; स्कॉटिश गवर्नमेंट की ओर से फर्स्ट मिनिस्टर के प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी श्री जॉन वेबस्टर तथा स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के सीनियर स्पेशल एडवाइजर, हेड ऑफ कर्मुनिंकेशंस एंड ऑफिशियल स्पोकसपर्सन, श्री रॉस इंग्लिष्टन भी उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की।

पश्चिम रेलवे द्वारा देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 5 का आयोजन

पश्चिम रेलवे द्वारा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) तथा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 5 का आयोजन किया जा रहा है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों और कारखानों में कई शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और सुविधाजनक बनाया गया है, जिससे पेंशनभोगी बिना पेंशन कार्यालय जाए, भारत में कहीं से भी और किसी भी समय अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ज़रनरे



कर सकते हैं। रेलवे पेंशनभोगी सरल 'फेस ऑथेंटिकेशन' तकनीक का उपयोग करके किसी भी एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइस के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य पेंशनभोगियों के बैंकों में जाने और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता को न्यूनतम करना है। विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित डीएलसी शिविरों को पश्चिम रेलवे में

उत्कृष्ट प्रतिसाद मिला है। सभी रेलवे पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, आसानी से तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। पेंशनभोगी अपने निकटतम डीएलसी शिविर में जा सकते हैं, जबकि आवश्यकता को न्यूनतम करना है। विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित डीएलसी शिविरों को पश्चिम रेलवे में

चीनी के शुल्क मुक्त आयात की समयसीमा बड़ी, अब 31 दिसंबर तक मिलेगी छूट

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) व्यवस्था के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात पर मिलने वाली शुल्क छूट को अब 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह सुविधा 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी। समयसीमा बढ़ने से आयातकों, रिफाइनरियों और कारोबारियों को विदेश से चीनी की इस खेप मंगाने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार ने 20 अगस्त को टीआरक्यू व्यवस्था के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। हालांकि, अब तक लगभग 2.6 लाख टन चीनी का ही आयात हो सका है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी मात्रा का आयात होने की संभावना को देखते हुए सरकार ने छूट की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू

बाजार में चीनी की कीमतों के बीच अंतर होने के कारण आयातकों को विदेश से चीनी खरीदने में अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते आयात की गति धीमी रही। अब समयसीमा बढ़ने से कारोबारियों को खरीदारी और खेप की आपूर्ति को योजना बनाने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। सरकार का यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब घरेलू चीनी उत्पादन को लेकर अनुमान में मदद कमी और आगामी महीनों में मांग बढ़ने की आशंका के बीच आपूर्ति व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों, बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों और अन्य खाद्य वस्तुओं के निर्माण में चीनी की खपत बढ़ जाती है। इस दौरान खुदरा बाजार के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मांग भी बढ़ती है। ऐसे में बाजार में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध रहना ज़रूरी माना जा रहा है। सरकार आयात के विकल्प को खुला रखकर मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। विपणन वर्ष 2025-26 में देश का

चीनी उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं, घरेलू खपत की सालाना मांग 280 से 285 लाख टन के बीच रहने की संभावना है। उत्पादन और मांग के इन अनुमानों के बावजूद त्योहारी से कारोबारियों को खरीदारी और खेप की आपूर्ति को ध्यान में लिए अधिक समय मिल सकेगा। सरकार का यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब घरेलू चीनी उत्पादन को लेकर अनुमान में मदद कमी और आगामी महीनों में मांग बढ़ने की आशंका के बीच आपूर्ति व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों, बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों और अन्य खाद्य वस्तुओं के निर्माण में चीनी की खपत बढ़ जाती है। इस दौरान खुदरा बाजार के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मांग भी बढ़ती है। ऐसे में बाजार में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध रहना ज़रूरी माना जा रहा है। सरकार आयात के विकल्प को खुला रखकर मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। विपणन वर्ष 2025-26 में देश का

और कीमतों में अनावश्यक तेजी की स्थिति न बने। स्टॉक सीमा के जरिए बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा पर नियंत्रण रखने और आपूर्ति व्यवस्था को नियमित बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। चीनी के आयात की समयसीमा बढ़ाने और स्टॉक सीमा लागू करने जैसे कदमों के माध्यम से सरकार मांग तथा आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात व्यावहारिक रहता है और निर्धारित मात्रा में खेप समय पर पहुंचती है, तो घरेलू बाजार में उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, चीनी की खुदरा कीमतों पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह आयात की वास्तविक मात्रा, घरेलू उत्पादन, कारोबारियों की खरीद और बाजार में मांग की स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल, 31 दिसंबर तक शुल्क छूट मिलने से आयातकों को अतिरिक्त समय के बीच आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए सरकार के पास एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध रहेगा।

स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी सहित प्रतिनिधिमंडल गुजरात की यात्रा पर

गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के सर्वांगीण विकास, वित्तीय सेवाओं, निवेश तथा निर्यात के विभिन्न क्षेत्रों से श्री जॉन स्विनी प्रभावित

गांधीनगर : भारत और देश में विकास के रोल मॉडल तथा ग्रोथ इंजन के रूप में पहचाने जाने वाले गुजरात में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी की अध्यक्षता में कुल 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल 22 से 25 अक्टूबर के दौरान गुजरात की यात्रा पर आया है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गांधीनगर में तैयार की गई विश्वस्तरीय गिफ्ट सिटी का श्री जॉन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रत्यक्ष दौरा किया।

इस दौरे के दौरान गिफ्ट सिटी के सर्वांगीण विकास, अलग-अलग वित्तीय सेवाओं, निवेश तथा निर्यात के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके श्री जॉन स्विनी तथा प्रतिनिधिमंडल प्रभावित हुआ।

इसके अलावा, गिफ्ट सिटी में



सुविधाओं की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए सड़कों की बार-बार खुदाई की जाती है, जिससे नागरिकों को असुविधा

होती है और शहर की सुंदरता भी खराब होती है। इस पारंपरिक समस्या के स्थायी समाधान के रूप में गिफ्ट

तहत सभी सेवाओं का नेटवर्क जमीन के नीचे स्थापित किया गया है, जिससे सड़कों पर खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ती।

यूटिलिटी टनल सिस्टम की मुख्य विशेषताएं :

जमीन का आदर्श उपयोग : टनल के लिए जमीन की एक छोटी-सी पट्टी का ही उपयोग होता है। इसके ऊपर की जगह का उपयोग बस स्टॉप, पेडेस्ट्रियन वॉक-वे, बैठने की जगहों तथा छोटी दुकानों या कियोस्क के लिए किया जा सकता है।

सुविधाओं का वर्गीकरण : टनल के लिए जमीन की एक छोटी-सी पट्टी का ही उपयोग होता है। इसके ऊपर की जगह का उपयोग बस स्टॉप, पेडेस्ट्रियन वॉक-वे, बैठने की जगहों तथा छोटी दुकानों या कियोस्क के लिए किया जा सकता है।

टनल की संरचना :

टनल के ऊपरी हिस्से में बैकअप सिस्टम वाले इलेक्ट्रिकल केबल और निचले हिस्से में पानी, कचरा निपटान तथा संचार लाइनें व्यवस्थित की गई हैं।

समर्पित कॉरिडोर : सुरक्षा के कारणों से सीवेज (गटर), स्टॉर्मवॉटर और गैस पाइपलाइन को टनल के बाहर एक अलग समर्पित कॉरिडोर में रखा गया है।

एससीएडीए द्वारा डिजिटल मॉनिटरिंग समग्र यूटिलिटी टनल की निगरानी सेंट्रल कंट्रोल रूम से एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) टेक्नोलॉजी के माध्यम से 24 घंटे की जाती है। यदि किसी क्षेत्र में तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो कंट्रोल रूम द्वारा मैनेजर्स टीम को तुरंत सूचित किया जाता है, जिससे सड़क पर यातायात को बाधित किए बिना तेजी से मरम्मत करना संभव होता है।

भविष्यलक्षी योजना और विस्तार : शहर के भविष्य के विकास और नई

बनने वाली इमारतों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस टनल की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, पूरी गिफ्ट सिटी में कुल 16 किलोमीटर लंबी यूटिलिटी टनल बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 5.5 किलोमीटर का नेटवर्क वर्तमान में पूरी तरह कार्यरत है। जबकि अन्य 5.5 किलोमीटर टनल का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। शेष हिस्सा शहर के चरणबद्ध विकास के साथ पूरा किया जाएगा। नई बनने वाली इमारतों को बेसमेंट के माध्यम से सीधे इस टनल नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है।

गिफ्ट सिटी की यह यूटिलिटी टनल केवल एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण-अनुकूल, सड़क पर यातायात को बाधित किए बिना तेजी से मरम्मत करना संभव होता है।

भविष्यलक्षी योजना और विस्तार : शहर के भविष्य के विकास और नई

भावनगर मंडल के 7 रेलवे स्टेशनों पर नए कवर शेड का निर्माण, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंडल के कुंडली, लाठीदड, अलमपर, वढवाण सिटी, सोनगढ़, खोडियार मंदिर और राणपुर रेलवे स्टेशनों पर नए कवर शेड का निर्माण किया गया है। इससे यात्रियों को धूप और बारिश जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियों से राहत मिलेगी तथा स्टेशन पर प्रतीक्षा करना अधिक सुविधाजनक होगा।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में तथा वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (सं.) श्री डी. एस. यादव की देखरेख में इन यात्री सुविधा संबंधी कार्यों को पूरा किया गया है। इन शेड के निर्माण से संबंधित स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हुई है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर



श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भावनगर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विकास एवं विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर

बनाने तथा पुनर्विकास कार्यों के माध्यम से यात्रा अनुभव को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्टेशन परिसरों के उन्नयन तथा यात्री संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अब सरकारी ई-प्रमाणपत्रों पर ही दिखाई देगी आधिकारिक राउंड सील, नागरिकों को मिलेगी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति !

प्रमाणपत्र पर मुहर लगवाने की भागदौड़ और समय का व्यय कम करने के लिए गुजरात सरकार का निर्णय

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा डिजिटल सेवाओं को और अधिक सरल, तेज तथा नागरिक-केन्द्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के 21 अक्टूबर, 2026 के परिपत्र के अनुसार डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाने वाले सभी प्रमाणपत्रों पर उन्हें जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के कार्यालय के विवरण के साथ आधिकारिक गोल मुहर (Round Seal) दर्शाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद उस पर मुहर लगवाने के लिए संबंधित कार्यालय में अलग से जाने की आवश्यकता कम करने का मार्ग प्रशस्त होगा। डिजिटल गुजरात 2.0 के अंतर्गत सरकारी सेवाओं को शुरु करने से अंत तक डिजिटल, सुगम और कारगरहित बनाने के प्रयासों को भी इससे गति मिलेगी।



दर्शाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुहर के साथ प्रमाणपत्र को मंजूरी देने वाले सक्षम अधिकारी के कार्यालय का पूरा विवरण भी दर्शाया जाएगा।

डिजिटल गुजरात 2.0 को मिलेगी गति

राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए सबसे अधिक आवश्यक और बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली सरकारी सेवाओं की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए

गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) और बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) का कार्य शुरू किया गया है। 'डिजिटल-बाई-डिफॉल्ट' विभागों के अंतर्गत सेवा वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप प्रदान करके डिजिटल गुजरात 2.0 के साथ एकीकृत करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।

नागरिकों को होगा सीधा लाभ **»**मुहर लगवाने के लिए सरकारी कार्यालय में अतिरिक्त चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। **»**समय, यात्रा और श्रम की बचत होगी।

»प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद की अतिरिक्त औपचारिकताओं को कम करने में मदद मिलेगी। **»**प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के कार्यालय के विवरण और आधिकारिक मुहर से दस्तावेज की पहचान अधिक स्पष्ट होगी। **»**ऑनलाइन सरकारी सेवाएं अधिक सुगम बनेंगी और कारगरहित प्रशासन को प्रोत्साहन मिलेगा।

कार्यान्वयन के लिए विभागीय समन्वय

जीएडी के परिपत्र के अनुसार संबंधित विभागों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद डिजिटल पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी विकास करके इस व्यवस्था को सिस्टम में लागू किया जाएगा। इस प्रकार, डिजिटल गुजरात 2.0 अंतर्गत ई-प्रमाणपत्रों पर आधिकारिक गोल मुहर दर्शाने की यह पहल सरकारी सेवाओं में नागरिकों की सुविधा बढ़ाने और अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।



अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना और किसी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय करना था। तलाशी के दौरान एक ठिकाने से आईईडी जैसी संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और अन्य

सामान मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में जांच तेज की। आईईडी को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल विस्फोट कर जान-माल को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा

सकता है। ऐसे में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने पर सुरक्षा बल निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे सुरक्षित करने और उसकी प्रकृति की पुष्टि करने की कार्रवाई करते हैं। हालांकि, बरामद सामग्री की पूरी जानकारी और

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के लिए भुवनेश्वर में रोड शो आयोजित हुआ, औद्योगिक सहयोग के अवसरों पर बल दिया गया

भुवनेश्वर रोड शो में सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और अत्याधुनिक मैनुफैक्चरिंग (उत्पादन) क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर विशेष बल

गांधीनगर : भुवनेश्वर के विवांता होटल में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (बीजीजीएस) 2027 अंतर्गत रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें गुजरात की औद्योगिक शक्ति केन्द्र में रही। इस रोड शो में निवेश, टेक्नोलॉजी साझेदारी और मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाएँ तलाशने के लिए अग्रणी उद्योगपतियों व सरकारी प्रतिनिधि एकत्र हुए। रोड शो से पहले गुजरात सरकार के मंत्री डॉ. जयराम गामित, गुजरात के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री लोचन सेहरा, आईएसएस तथा गुजरात के अन्य प्रसिद्धि महापुरुषों ने भुवनेश्वर के प्रमुख संस्थानों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठके आयोजित कीं। इन बैठकों में ज़िंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के रेंजिडेंट डायरेक्टर शशिभूषण उपाध्याय, सीएसपीसी (ओडिशा) के मुख्य कॉर्पोरेट रणनीतिकार पार्थ पटनायक, वेल्सपन के सीओ एवं निदेशक सुभाषचंद्र साहू, अवाडा एनर्जी की प्रियदर्शिनी महापात्रा, ग्योरेवे के सह-संस्थापक एवं सीओ सलोषी साहू, वर्ल्ड स्किल सेंटर की एसडीटी एवं सीओओ श्रीमती रश्मि साहू तथा नैल्को के निदेशक जगदीश अरोड़ा सहित अन्य प्रतिनिधि



उपस्थित रहे। इन बैठकों में गुजरात एवं ओडिशा के बीच औद्योगिक सहयोग, उपरती प्रौद्योगिकियों तथा संभावित साझेदारियों को लेकर विचारों का आदान-प्रदान करने पर चर्चा की गई। रोड शो के दौरान श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री लोचन सेहरा, आईएसएस ने बीजीजीएस 2027 पर प्रेजेंटेशन दिया। इसके साथ ही गुजरात के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष लघु फिल्म भी दिखाई गई। उद्योग प्रतिनिधियों ने राज्य में व्यावसायिक अवसरों तथा औद्योगिक विकास को लेकर अपनी व्यावहारिक अनुभव तथा मत भी प्रस्तुत किए। सेमिनार को संबोधित करते हुए गुजरात सरकार के उद्योग एवं एमएसएमई राज्य मंत्री डॉ. जयराम गामित ने दोनों राज्यों के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग

की संभावनाओं पर बल दिया। डॉ. जयराम गामित ने अपने संबोधन में कहा, "ओडिशा ने खनिज, धातु और एल्यूमिनियम क्षेत्र में एक अग्रणी केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जबकि गुजरात के पास औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल कनेक्टिविटी क्षेत्र में मजबूत क्षमताएँ हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारे उद्योगों, उद्यमियों और युवा प्रतिभाओं को साथ लाकर हम नवाचार, रोजगार और साझा समृद्धि के लिए नए अवसर सृजित कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी आगे बढ़ रही हैं, तब भुवनेश्वर और पूरे ओडिशा के उद्यमों, स्टार्टअप तथा को अधिक मजबूत बनाएँ।" गुजरात भारत के कुल मैनुफैक्चरिंग आउटपुट में 17 प्रतिशत और माल-सामान के निर्यात में 25 प्रतिशत योगदान देता है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान ओडिशा के स्थापित ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग इकोसिस्टम को गुजरात के उपरते सेमीकंडक्टर क्षेत्र,

अत्याधुनिक मैनुफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के अवसरों पर विशेष बल दिया गया। 11वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10 से 12 जनवरी, 2027 तक गांधीनगर में "विकसित गुजरात-शेरींग ग्लोबल फ्यूचर" (विकसित गुजरात-वैश्विक भविष्य का निर्माण) थीम अंतर्गत आयोजित होगी। यह समिट उद्योग जगत, नीति-निर्माताओं और औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाएगी। भुवनेश्वर का यह रोड शो गुजरात और ओडिशा के बीच औद्योगिक संबंधों को केवल बातचीत तक सीमित न रखते हुए सार्थक व्यावसायिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ है। आज जब बीजीजीएस 2027 की तैयारियाँ आगे बढ़ रही हैं, तब भुवनेश्वर और पूरे ओडिशा के उद्यमों, स्टार्टअप तथा औद्योगिक संस्थानों को अपनी विशेषज्ञता, विचारों और साझेदारी की प्राथमिकताओं के साथ गांधीनगर आने तथा अंतरराज्यीय मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) और भारत के औद्योगिक विकास के अगले चरण में योगदान देने के लिए हार्दिक आमंत्रण दिया जाता है।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027: राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी को वाइब्रेंट समिट का आमंत्रण



गांधीनगर : गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास और रोजगार, ग्राम विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री कुंवरजीभाई बाबलिया ने शुक्रवार को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा तथा माननीय उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी से मुलाकात की। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 से पूर्व जयपुर में उच्चस्तरीय रोड-शो के लिए माननीय मंत्री श्री कुंवरजीभाई बाबलिया एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राजस्थान के दौरे पर हैं। GUVNL की प्रबंध निदेशक श्रीमती शालिनी अग्रवाल (IAS) भी गुजरात सरकार के इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राजस्थान दौरे पर हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट श्रृंखला

का 11वां संस्करण वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 10 से 12 जनवरी को हो रहा है। यह समिट वैश्विक निवेशक, उद्योगपति, नीति-निर्धारक सहित विविध क्षेत्र के अग्रणीयों को एक साझा वैश्विक मंच प्रदान करने का विश्वस्तरीय माध्यम है। गुजरात-भारत का यह साझा वैश्विक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 से पूर्व जयपुर में उच्चस्तरीय रोड-शो के लिए माननीय मंत्री श्री कुंवरजीभाई बाबलिया एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राजस्थान के दौरे पर हैं। GUVNL की प्रबंध निदेशक श्रीमती शालिनी अग्रवाल (IAS) भी गुजरात सरकार के इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राजस्थान दौरे पर हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट श्रृंखला

गुजरात सरकार और स्कॉटलैंड सरकार के बीच गांधीनगर में महत्वपूर्ण एमओयू हुआ

»मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और स्कॉटलैंड गवर्नमेंट के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी की प्रेरक उपस्थिति **»**परस्पर मित्रता और समझ का सेतु **सुदृढ़ बनाकर पीपल कनेक्ट, इकोनॉमिक रिलेशन्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड इन्क्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा इनोवेशन सेक्टर में सहयोग के अवसर विकसित किए जाएंगे**

»स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, स्किलिंग एंड रिसर्च तथा कल्चरल एक्सचेंज के क्षेत्रों में गुजरात-स्कॉटलैंड के बीच सहयोग की संभावनाओं पर फोकस

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

»ऑफशोर एनर्जी में ग्लोबल लीडर के रूप में स्कॉटलैंड की विशेषज्ञता के अध्ययन के लिए गुजरात का डेलिगेशन स्कॉटलैंड जाएगा

»गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में देश का अग्रणी राज्य है, जिसे स्कॉटलैंड का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सहयोग और गति देगा

»गुजरात-स्कॉटलैंड के बीच हुआ एमओयू कल्चर, स्पोर्ट्स, एनर्जी और लाइफ साइसेज के क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा : स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और स्कॉटलैंड सरकार के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी की उपस्थिति में गांधीनगर में गुजरात सरकार और स्कॉटलैंड सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ। इस एमओयू अंतर्गत गुजरात और स्कॉटलैंड के बीच परस्पर मित्रता एवं समझ का सेतु सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ पीपल कनेक्ट, इकोनॉमिक रिलेशन्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड इन्क्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा इनोवेशन और समृद्धि के लिए सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इतना ही नहीं, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग तथा म्यूचुअल इंटररेस्ट के क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के अवसर विकसित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री के साथ गांधीनगर में स्कॉटलैंड सरकार के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी और उनके डेलिगेशन की शिष्टाचार भेंट के दौरान यह एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने एमओयू का परस्पर आदान-प्रदान किया।

गुजरात वर्ष 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स का ग्लासगो में सफल आयोजन करने के स्कॉटलैंड के अनुभव, वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिटनेस कल्चर को प्रोत्साहन जैसे विषयों पर गुजरात को स्कॉटलैंड का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करने में यह एमओयू उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

गुजरात और स्कॉटलैंड के बीच व्यवसाय एवं संपर्क सहयोग बढ़ाने, व्यापार एवं



निवेश के अवसरों को प्रोत्साहित करने तथा इनोवेशन, उद्यमिता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ-साथ दोनों पक्षों की द्विपक्षीय विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर परस्पर भागीदारी के क्षेत्रों की पहचान करने संबंधी विषयों को इस एमओयू में शामिल किया गया है। गुजरात और स्कॉटलैंड के समान हितों वाले सेक्टर में आपसी सहयोग से आगे बढ़ने में भी यह एमओयू उपयुक्त सिद्ध होगा। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर श्री जॉन स्विनी ने विश्वास व्यक्त किया कि कल्चर, स्पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और लाइफ साइसेज के क्षेत्रों में गुजरात-स्कॉटलैंड के बीच हुए इस एमओयू से विकास के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने विशेष रूप से ऑफशोर एनर्जी के क्षेत्र में स्कॉटलैंड की एक्सपर्टीज का लाभ गुजरात को उपलब्ध कराने की उत्सुकता दर्शाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संदर्भ में

प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुजरात समग्र देश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इतना ही नहीं, देश के सबसे लंबे समुद्र तट वाले गुजरात में ऑफशोर एनर्जी की भी प्रचुर संभावनाएँ और क्षमताएँ विद्यमान हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान यह सुझाव भी दिया कि ऑफशोर एनर्जी क्षेत्र में ग्लोबल लीडर स्कॉटलैंड की एक्सपर्टीज से मार्गदर्शन प्राप्त करने और उसका अध्ययन करने के लिए गुजरात का एक डेलिगेशन स्कॉटलैंड का दौरा करे। उन्होंने एमओयू में शामिल विषयों का विवरण देते हुए कहा कि अधिक सस्टेनेबल इकोनॉमी की दिशा में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए

संबंधित व्यवसायों, संस्थानों और विशेषज्ञों के बीच संपर्क मजबूत करने, नॉलेज, एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करने तथा नवाचार, कौशल विकास और व्यावसायिक एवं संस्थागत भागीदारी के अवसर विकसित करने में भी यह एमओयू उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात और स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच कनेक्टिविटी, शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग से ज्ञान व कौशल प्रोत्साहित किया जाएगा और परस्पर हित वाले क्षेत्रों में विशारथियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और संस्थाओं के संबंध करने में भी यह एमओयू उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्य सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि संस्कृति, विरासत और सृजनवात्मक उद्योगों के माध्यम से गुजरात व स्कॉटलैंड के लोगों के बीच आपसी समझ तथा दीर्घकालीन संबंधों को प्रोत्साहित करने का विषय भी एमओयू में शामिल है। उद्योग विकास के कार्यकारी अग्र मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि इस एमओयू के परिणामस्वरूप एजुकेशन एंड स्किलिंग, स्पोर्ट्स एंड एनर्जी सेक्टर में डायलॉग, ट्रस्ट तथा मीनिंगफुल पार्टनरशिप विकसित होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, शहरी विकास एवं शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के अग्र प्रधान सचिव डॉ. विक्रान्त पांडे तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव सहभागी हुए।